



CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE : 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,

Near Okhla Industrial Area Phase-III,

Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020

Tel : +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-20887232

Website : www.cordscable.com ; Email : ccil@cordscable.com

CIN : L74999DL1991PLC046092

Date: 24.03.2025

Listing Department (Compliance Cell), National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051 Scrip Code: CORDSCABLE	Listing Department (Compliance Cell), Bombay Stock Exchange Ltd. Floor 25, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Scrip Code: 532941
--	--

Sub.: SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 - Closure of Trading Window.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, as amended, please find enclosed herewith copy of newspaper publication regarding intimation of closure of trading window from Tuesday, 1st April, 2025 till 48 hours after the declaration of Audited Financial Results along with Auditors Report for the 4th Quarter/ 12 months ended on 31st March, 2025 is made public.

This is for your kind information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

For Cords Cable Industries Ltd.

GARIMA PANT
Company Secretary

Company Secretary

Works :

(UNIT I) : A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003177

(UNIT II) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003176

				प्रप्र स्रं. 3
				[विनियम-13 (1)(ए) देखें]
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)				
प्रथम तल, एएससीओ नं. 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित किया गया है)				
प्रकरण सं. : ओए/1467/2024				
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।				एक्स. नं.: 25613
यस बैंक विरुद्ध मनोज मनोज				
प्रतिवादी सं. 2- इन्डु पत्नी मनोज निवाली ग्राम : गवालीसर, आउटर केनाल ऑफ वाटर के समीप, झज्जर, हरियाणा- 124103 न्यायालयी आदेश (समन्स)				
जबकि, ओए/1467/2024, दिनांक 20/02/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।				
जबकि, यह माननीय अधिकरण र. 32.03.446.19/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।				
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादीयों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-				
(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;				
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 39 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संसितियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संसितियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;				
(3) आपको, संसितियों की कुकीं के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के संबंध रहने तक, मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 39 के तहत प्रकट की गई प्रतियुत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संसितियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;				
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतियुति हित सुचित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 39 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं संसितियों को बेचना, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;				
(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतियुत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संसितियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री-आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री-आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतियुति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।				
आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 05-05-2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा।				
आज दिनांक : 12/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।				
ऋण वसूली अधिकरण-1।, चंडीगढ़				

				प्रप्र स्रं. 3
				[विनियम-13 (1)(ए) देखें]
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)				
प्रथम तल, एएससीओ नं. 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित किया गया है)				
प्रकरण सं. : ओए/1509/2024				
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।				एक्स. नं.: 25281
यस बैंक विरुद्ध अमरपाल सिंह सिंह				
अमरपाल सिंह सिंह जी/अबलू/एए/ओ- दीवान सिंह अमरपाल सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी कंवारी 30 रोहतक हरियाणा- 125037, रोहताक, हरियाणा न्यायालयी आदेश				
जबकि, ओए/1509/2024, दिनांक 30/01/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।				
जबकि, यह माननीय अधिकरण र. 41.55,978.35/- के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।				
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादीयों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-				
(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;				
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 39 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संसितियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संसितियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;				
(3) आपको, संसितियों की कुकीं के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के संबंध रहने तक, मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 39 के तहत प्रकट की गई प्रतियुत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संसितियों का लेन-देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;				
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतियुति हित सुचित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 39 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं संसितियों को बेचना, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;				
(5) आप व्यवसाय के सामान				

JOINT ACTION COMMITTEE ON DELIMITATION

JAC for extending freeze on constituencies by 25 years

Meet an eye on '26 polls as DMK has no achievements: FM

PRESS TRUST OF INDIA
Chennai, March 22

ASSERTING THAT THE proposed delimitation exercise based on population would not be "fair" to southern states, the DMK-led Joint Action Committee meeting on Saturday demanded that the Centre should extend the freeze on Parliamentary constituencies, based on the 1971 Census population, by another 25 years and decided to submit a joint representation to Prime Minister Narendra Modi during the ongoing Parliamentary session.

A political consensus also emerged to fight against "population" as the yardstick to determine delimitation and it was resolved during the meeting, which was held to ensure "fair delimitation", not to lose representation for southern states. Politically, the meeting, which was attended by three chief ministers, a deputy CM and leaders of 14 parties including the BRS, BJD and SAD from



(From left) Kerala chief minister Pinarayi Vijayan, Punjab CM Bhagwant Mann, Tamil Nadu CM MK Stalin and Telangana CM Revanth Reddy at a meeting of states over the proposed delimitation of Parliamentary seats, in Chennai on Saturday

six states in a show of solidarity on the issue, was a shot in the arm for Chief Minister M K Stalin and his party DMK, ahead of the Assembly election in Tamil Nadu next year.

"The upcoming or future population-based delimitation of constituencies based on the next census will greatly affect a few states. We should all be absolutely sure that delimitation based on the current popu-

lation cannot be accepted," Stalin asserted. He also said a legal option could be explored and favoured setting up an expert panel to draw up the political and legal action plan.

Addressing the meeting, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan termed the proposed delimitation as a 'sword of Damocles' hanging over the states, especially in southern India, which implemented pro-

grammes to control the population. He urged the Centre to engage in "meaningful dialogues" before going ahead with the process. Delimitation, if done after the Census, will lead to an increase in seats for northern states and a reduction for southern states. "Such a cut in seats for the south and an increase for the north will suit the BJP as it holds greater influence in the north," he claimed. Recently, Union Home Minister Amit Shah had accused Stalin of spreading "misinformation," over the delimitation issue and assured that southern states will not lose a "single Parliamentary seat." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman charged the DMK was raising "emotional" issues like alleged Hindi imposition and delimitation as it had nothing to showcase as its own achievements before the people during next year's Assembly polls in Tamil Nadu. The DMK, however, described the meeting as a "historic first," in the annals of independent India, involving 7 states including Tamil Nadu and 14 political parties. "DMK President (Stalin) is deciding national politics, the JAC resolution is causing political tremors in Delhi," the party said.

Cash recovery: Delhi HC CJ submits report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, March 22

DELHI HIGH COURT'S chief justice DK Upadhyaya has submitted a report to Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna in connection with the alleged discovery of cash from Justice Yashwant Varma's official residence. Justice Upadhyaya had commenced an in-house enquiry procedure over the incident, collecting evidence and information. He submitted his report to the CJI on Friday after talking to all the authori-

ties concerned, including the fire department and police. The apex court collegium will look into the report and may initiate further action. The purported discovery of a huge stash of cash happened following a fire at Justice Varma's Lutyens' Delhi residence at around 11:35 pm on the night of Holi on March 14, prompting the fire department personnel to rush to the spot and douse the flames. In a statement on Friday, the Supreme Court said the Delhi High Court chief justice had

initiated an in-house inquiry against Justice Varma and separately, there was a proposal to transfer the judge to the Allahabad High Court. "There is misinformation and rumours are being spread with regard to the incident at the residence of Justice Yashwant Varma," the statement said. Upon receiving the information, the apex court said Justice Upadhyaya "commenced the in-house enquiry procedure, collecting evidence and information". Justice Upadhyaya was stated to have commenced the inquiry prior to a

meeting of the apex court collegium on March 20. The Supreme Court said the proposal for transferring Justice Varma was examined by the apex court collegium comprising the CJI and the four senior-most judges on March 20 and thereafter, letters were shot off to the consultee judges of the top court and the chief justices of the high courts concerned, besides Justice Varma. "Responses received will be examined and, thereupon, the collegium will pass a resolution," the court said.

IPL fever on, as is tax heat on online gaming

DGGI has so far blocked 166 mule accounts linked to these platforms. Three such persons have been arrested till now, and an investigation against more such individuals is under progress. Under the GST law, 'online money gaming', being actionable claim, is classified as a supply of 'goods' and is subject to a 28% tax. Entities operating in this sector are required to register under the GST.

With the upcoming IPL season, enforcement actions by tax officers will be more stringent to curb illicit gaming operations, the ministry said, urging people to engage only with regulated e-gaming platforms. The ministry said non-compliance by foreign entities distorts fair competition, harms local businesses, and skews the market. These unscrupulous foreign entities circumvent restrictions by creating new web addresses. "Investigations also revealed that these companies operated through 'mule' bank accounts to process transactions. Funds collected through mule accounts leave the potential to be funnelled into illicit activities, which may also be dangerous for the national security point of view," the ministry added. The ministry further said, "It has been observed that many Bollywood celebrities and cricketers, along with YouTube, WhatsApp, and Instagram influencers, are found endorsing these platforms, and, therefore, the public is advised to remain cautious and not engage with offshore online money gaming platforms as it may jeopardise their personal finances and indirectly support activities that undermine financial integrity and national security".

Sweet & tangy summer for beer lovers

"OUR MOMENTUM IN the premium category continued with volume growth rising by 33%, bringing the YTD growth rate to 35%. There's been market share gains for the quarter, both on an overall basis as well as in the premium segment," he explained. With the growing pride in local flavours and willingness to explore premium options, Gupta sees significant growth potential for this segment. "There is also an increased interest for beers with low bitterness, making flavoured variants a preferred choice," he added.

Similarly, Goa's Latam-barcecm Brewers recently announced a partnership with Taiwan's Jim and Dad's Brewing Company to produce what it claims to be India's first bottled 'tea beer', Maka di Oolong Blanche. "The idea behind our tea-infused beer was to bring together the best of two of the world's most beloved beverages — beer and tea. By balancing flavours, we have crafted a brew that offers both depth and refreshment, ensuring that neither element overpowers the other," said Aditya Ishan Varshnei, CEO of Latam-barcecm Brewers. "Our goal was to create an authentic, world-class beer perfect for those who appreciate sophistication in every sip while still craving a light, invigorating drinking experience," he added. It's exciting to see consumers becoming experimental and open to innovative flavours, as per Atul Kumar Singh, co-founder &

JOINT ACTION COMMITTEE ON DELIMITATION

JAC for extending freeze on constituencies by 25 years

Meet an eye on '26 polls as DMK has no achievements: FM

PRESS TRUST OF INDIA
Chennai, March 22

ASSERTING THAT THE proposed delimitation exercise based on population would not be "fair" to southern states, the DMK-led Joint Action Committee meeting on Saturday demanded that the Centre should extend the freeze on Parliamentary constituencies, based on the 1971 Census population, by another 25 years and decided to submit a joint representation to Prime Minister Narendra Modi during the ongoing Parliamentary session.

A political consensus also emerged to fight against "population" as the yardstick to determine delimitation and it was resolved during the meeting, which was held to ensure "fair delimitation", not to lose representation for southern states. Politically, the meeting, which was attended by three chief ministers, a deputy CM and leaders of 14 parties including the BRS, BJD and SAD from



(From left) Kerala chief minister Pinarayi Vijayan, Punjab CM Bhagwant Mann, Tamil Nadu CM MK Stalin and Telangana CM Revanth Reddy at a meeting of states over the proposed delimitation of Parliamentary seats, in Chennai on Saturday

six states in a show of solidarity on the issue, was a shot in the arm for Chief Minister M K Stalin and his party DMK, ahead of the Assembly election in Tamil Nadu next year.

"The upcoming or future population-based delimitation of constituencies based on the next census will greatly affect a few states. We should all be absolutely sure that delimitation based on the current popu-

lation cannot be accepted," Stalin asserted. He also said a legal option could be explored and favoured setting up an expert panel to draw up the political and legal action plan.

Addressing the meeting, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan termed the proposed delimitation as a 'sword of Damocles' hanging over the states, especially in southern India, which implemented pro-

grammes to control the population. He urged the Centre to engage in "meaningful dialogues" before going ahead with the process. Delimitation, if done after the Census, will lead to an increase in seats for northern states and a reduction for southern states. "Such a cut in seats for the south and an increase for the north will suit the BJP as it holds greater influence in the north," he claimed. Recently, Union Home Minister Amit Shah had accused Stalin of spreading "misinformation," over the delimitation issue and assured that southern states will not lose a "single Parliamentary seat." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman charged the DMK was raising "emotional" issues like alleged Hindi imposition and delimitation as it had nothing to showcase as its own achievements before the people during next year's Assembly polls in Tamil Nadu. The DMK, however, described the meeting as a "historic first," in the annals of independent India, involving 7 states including Tamil Nadu and 14 political parties. "DMK President (Stalin) is deciding national politics, the JAC resolution is causing political tremors in Delhi," the party said.

Cash recovery: Delhi HC CJ submits report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, March 22

DELHI HIGH COURT'S chief justice DK Upadhyaya has submitted a report to Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna in connection with the alleged discovery of cash from Justice Yashwant Varma's official residence. Justice Upadhyaya had commenced an in-house enquiry procedure over the incident, collecting evidence and information. He submitted his report to the CJI on Friday after talking to all the authori-

ties concerned, including the fire department and police.

The apex court collegium will look into the report and may initiate further action.

The purported discovery of a huge stash of cash happened following a fire at Justice Varma's Lutyens' Delhi residence at around 11:35 pm on the night of Holi on March 14, prompting the fire department personnel to rush to the spot and douse the flames. In a statement on Friday, the Supreme Court said the Delhi High Court chief justice had

initiated an in-house inquiry against Justice Varma and separately, there was a proposal to transfer the judge to the Allahabad High Court. "There is misinformation and rumours are being spread with regard to the incident at the residence of Justice Yashwant Varma," the statement said. Upon receiving the information, the apex court said Justice Upadhyaya "commenced the in-house enquiry procedure, collecting evidence and information". Justice Upadhyaya was stated to have commenced the inquiry prior to a

meeting of the apex court collegium on March 20. The Supreme Court said the proposal for transferring Justice Varma was examined by the apex court collegium comprising the CJI and the four senior-most judges on March 20 and thereafter, letters were shot off to the consultee judges of the top court and the chief justices of the high courts concerned, besides Justice Varma. "Responses received will be examined and, thereupon, the collegium will pass a resolution," the court said.

IPL fever on, as is tax heat on online gaming

DGGI has so far blocked 166 mule accounts linked to these platforms. Three such persons have been arrested till now, and an investigation against more such individuals is under progress. Under the GST law, 'online money gaming', being actionable claim, is classified as a supply of 'goods' and is subject to a 28% tax. Entities operating in this sector are required to register under the GST.

With the upcoming IPL season, enforcement actions by tax officers will be more stringent to curb illicit gaming operations, the ministry said, urging people to engage only with regulated e-gaming platforms. The ministry said non-compliance by foreign entities distorts fair competition, harms local businesses, and skews the market. These unscrupulous foreign entities circumvent restrictions by creating new web addresses. "Investigations also revealed that these companies operated through 'mule' bank accounts to process transactions. Funds collected through mule accounts leave the potential to be funnelled into illicit activities, which may also be dangerous for the national security point of view," the ministry added. The ministry further said, "It has been observed that many Bollywood celebrities and cricketers, along with YouTube, WhatsApp, and Instagram influencers, are found endorsing these platforms, and, therefore, the public is advised to remain cautious and not engage with offshore online money gaming platforms as it may jeopardise their personal finances and indirectly support activities that undermine financial integrity and national security."

Sweet & tangy summer for beer lovers

"OUR MOMENTUM IN the premium category continued with volume growth rising by 33%, bringing the YTD growth rate to 35%. There's been market share gains for the quarter, both on an overall basis as well as in the premium segment," he explained. With the growing pride in local flavours and willingness to explore premium options, Gupta sees significant growth potential for this segment. "There is also an increased interest for beers with low bitterness, making flavoured variants a preferred choice," he added.

Similarly, Goa's Latamarcem Brewers recently announced a partnership with Taiwan's Jim and Dad's Brewing Company to produce what it claims to be India's first bottled 'tea beer', Maka di Oolong Blanche. "The idea behind our tea-infused beer was to bring together the best of two of the world's most beloved beverages — beer and tea. By balancing flavours, we have crafted a brew that offers both depth and refreshment, ensuring that neither element overpowers the other," said Aditya Ishan Varshnei, CEO of Latamarcem Brewers. "Our goal was to create an authentic, world-class beer perfect for those who appreciate sophistication in every sip while still craving a light, invigorating drinking experience," he added. It's exciting to see consumers becoming experimental and open to innovative flavours, as per Atul Kumar Singh, co-founder & MD of homegrown beer brand Lone Wolf. "The change is largely